माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्श 2009–10 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूॅ।

1ण हमारी सरकार को सत्ता सम्भाले हुए एक साल का समय हो गया है और हमारी उपलब्धियों को प्रदेष की जनता सराह रही है। एक वर्श के कम समय में हमने राज्य की प्रगति तथा विकास के अनेक लक्ष्य प्राप्त किए हैं। हमारी सरकार का ध्येय है कि अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुरुप हिमाचल प्रदेष सामाजिक व आर्थिक विकास में भी सबसे ऊपर हो।

2ण 7 मार्च, 2008 को पिछला बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने आष्वासन दिया था कि वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने के साथ–साथ हम विकास की गति को भी तेज़ करेंगे। अनुत्पादक खर्चों में कमी तथा वित्तीय सुधारों के उच्च मानकों को अपनाते हुए हमनें षिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत विकास जैसे सभी अत्यावष्यक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजट आबंटित किया है। ऐसे संरचनात्मक निवेष में वृद्धि के साथ–साथ हमने महिलाओं, समाज के गरीब तथा सुविधा–रहित वर्गों की विषेश आवष्यकताओं का भी घ्यान रखा है। हमारी सरकार ने एक वर्श की अल्पावधि में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्षन राषि में 65 प्रतिषत की वृद्धि कर इसे 200/–रुपये से बढ़ाकर 330/– रुपये प्रतिमाह किया है। न्यूनतम दिहाड़ी को भी 47 प्रतिषत बढ़ाकर 75/–रुपये से 110 रूपये किया गया है।

आर्थिक परिदृष्य

3ण सभी मान्य सदस्य जानते हैं कि वर्श 2008 की अन्तिम तिमाही से विष्व की अर्थव्यवस्था में बड़ी हलचल रही है। राश्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति की ऊंची दर के पष्चात् निवेष के लिए धन की कमी तथा मंदी का रूझान रहा है। हिमाचल प्रदेष की निर्यातपरक औद्योगिक इकाईयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस सबके बावजूद हमारी सरकार ने राज्य

को तीव्र प्रगति के पथ पर डाला है। 2008–09 में 7.1 प्रतिषत राश्ट्रीय विकास दर के मुकाबले राज्य की विकास दर 7.7 प्रतिषत अनुमानित है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2007–08 के 32,220 करोड़ से बढ़कर 2008–09 में संभवतः 36,940 करोड़ रुपये होगा। हमारे ठोस राजकोशीय उपायों से अगले वर्श सकल घरेलू उत्पाद 45,000/– करोड़ रुपये से भी अधिक होगा। 2008–09 में प्रति व्यक्ति आय सम्भवतः 44,803 रुपये होगी, और 2009–10 में यह 50,000/– रुपये से भी अधिक हो जाएगी। अर्थात अगले वर्श हिमाचल प्रदेष में औसत घरेलू आय 20,000/– रुपये प्रतिमास से भी अधिक होगी। यह हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रों में समग्र समृद्धि का सूचक है।

4ण इस मान्य सदन को सूचित करते हुए मुझे विषेश प्रसन्नता है कि हमारी सरकार द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के आबंटन को प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा अधिक पारदर्षी बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप हम 600 करोड़ रूपये से भी अधिक के संसाधन जुटा पायेंगे। इस असाधारण कदम के कारण 2008–09 के वास्तविक वित्तीय घाटे को दर्षाए गए आंकड़ों से काफी कम किया जा सका है। 2008–09 का वर्श मज़बूत अर्थव्यवस्था का वर्श रहा है। इस वर्श, हमने सुनिष्चित किया है कि प्रदेष सरकार भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऋण सीमा के भीतर रहेगी और बजट से बाहर कोई भी ऋण नहीं लेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेन्षन भोगियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी के साथ–साथ हमने संषोधित वेतनमानों की प्रत्याषा में अन्तरिम राहत की अदायगी भी कर दी है। इसके बावजूद हमने बेहतर वित्तीय प्रबन्धन द्वारा सुनिष्चित किया है कि हमारे कार्यकाल के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सरकार के नाम एक भी दिन का 'ओवर ड्राफ्ट' नहीं हुआ है।

5ण तथापि, मैं मान्य सदन के सदस्यों को सचेत करना चाहूँगा कि आगामी वित्त वर्श प्रत्याषित संषोधित वेतनमान तथा पेन्षन दायित्वों के कारण भारी

वित्तीय चुनौतियों भरा होगा। चूंकि अगला वर्श बारहवें वित्त आयोग प्रदाय का अन्तिम वर्श है, अतः 2007–08 के मुकाबले 2009–10 में केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायतानुदान राषि 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा घटेगी। इसके अलावा, राश्ट्रीय स्तर पर विकास की गति में गिरावट तथा मंदी के कारण अगले वर्श केन्द्रीय करों के हिस्से में पिछले वर्शों की भान्ति वृद्धि नहीं हो पाएगी।

6ण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करके हमारी सरकार 2009–10 की वित्तीय चुनौतियों का पूरी तरह से सामना करने के लिए कटिबद्ध है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा कर एवं गैर कर आय में वृद्धि करने के लिए हमने आन्तरिक उपाय तलाषने षुरू कर दिए हैं। इनमें बिजली षुल्क के लिए यथामूल्य दरें अपनाना भी षामिल है। आबकारी एवं कराधान विभाग के कंप्यूटरीकरण द्वारा आगामी वर्श के दौरान हम राजस्व वसूलियों में हो रही हानि पर रोक लगाएंगे। निजी तथा व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण कर की दरों को पड़ोसी राज्यों की दरों के बराबर लाया जाएगा। पर्यावरण को बचाए रखना हमारी सरकार की महत्त्वपूर्ण नीति है। इसके लिए हम वाहनों की बढ़त पर नियन्त्रण के उद्देष्य से तथा बेहतर पर्यावरण रक्षा उपायों हेतु धन प्रदान करने के लिए पर्यावरण षुल्क लगाने के सम्भावित विकल्प तलाषेंगे।

वार्शिक योजना 2009–10

7ण अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट भाशण में मैंने विषेश रूप से उल्लेख किया था कि पिछली सरकार की कमज़ोर वित्तीय विरासत को हम राज्य के तीव्र विकास के आड़े नहीं आने देंगे। हमारी सरकार के आने के बाद सड़कों, पेयजल तथा सिंचाई परियोजनाओं, षिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से चल रहे विकास कार्य इस तथ्य की पुश्टि करते हैं कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है।

8ण आगामी वेतनमान संषोधन के आर्थिक प्रभाव के कारण 2009–10 की वित्तीय स्थिति को हमें मज़बूत वित्त प्रबन्धन से सम्भालना होगा।

अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करते हुए अगले वित्त वर्श के लिए हमनें 2700 करोड़ रुपये की वार्शिक योजना परिव्यय का प्रावधान किया है, जो इस वर्श के परिव्यय से 12.5 प्रतिषत अधिक है।

9ण अगले वित्त वर्श के लिए क्षेत्रवार प्राथमिकताएं हमने सदन के मान्य सदस्यों के साथ 15 व 16 जनवरी, 2009 को हुए गहन विचार–विमर्ष तथा अन्य सभी जांमीवसकमते से विचार–विमर्ष के आधार पर निर्धारित की हैं।

10ण 2009–10 की वार्शिक योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्श में हुए विकास को मज़बूत करने पर बल दिया जायेगा। चालू पूंजीगत कार्यों को षीघ्र पूरा करने तथा विद्यमान परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर समान बल देने के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रोत्साहित किया जाएगा। विभागों को अपने बजट प्रावधानों के अन्दर रहते हुए परिसम्पत्तियों के रख–रखाव की अपेक्षाओं को निर्धारित करने की छूट दी जाएगी। विभाग अपने पूंजीगत परिसम्पत्तियों की रख–रखाव योजना भी स्वंय तैयार करेंगे।

11ण अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार की उपलब्धियों तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बनाई गई नीतियों का उल्लेख करना चाहूँगा।

कृशि,बागवानी तथा सम्बद्ध गतिविधियां

12ण कृशि, बागवानी, पषुपालन तथा मछली पालन हिमाचल प्रदेष की जनता के जीवनयापन के मुख्य साधन हैं, जिनसे लगभग 70 प्रतिषत कामकाजी जनता को रोज़गार मिलता है। इसके दृश्टिगत हमारी सरकार राज्य के कृशकों के आर्थिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। नाबार्ड (छ।ठ।त्क्द्ध वित्तीय सहायता के माध्यम से हमने 353 करोड़ रुपये की श्पंडित दीन दयाल किसान–बागवान समृद्धि योजनाश आरम्भ कर दी है। इस योजना से लघु सिंचाई सुविधाओं तथा लगभग 29,000 जलवायु नियंत्रित 'पौली हाऊसिज़' के माध्यम से हमारे किसानों की नगदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। हमें विष्वास है कि इस योजना से स्वरोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा कृशि आय भी बढ़ेगी।

13ण सिंचाई सुविधाओं की कमी से कृशि उत्पादकता प्रभावित होती है। इस

कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार षाह नहर, सिद्धाथा, बल्हघाटी तथा चंगर सिंचाई परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। कार्यकारी एजेन्सियों की कार्यक्षमता के अनुरूप इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण वित्त पोशण के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लघु सिंचाई एवं भू तथा जल–संरक्षण गतिविधियों के लिए अगले वित्त वर्श में हमने 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इस प्रकार सिंचाई क्षेत्र के लिए 267 करोड़ रुपये का कुल योजना प्रावधान किया गया है, जो समग्र योजना परिव्यय का लगभग 10 प्रतिषत है।

14ण कृशि उत्पादकता में वृद्धि के दृश्टिगत, कृशि विभाग द्वारा किसानों में वितरण हेतु, उच्च उत्पादन गुणवत्ता वाले बीजों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये का विषेश बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया मिट्टी परीक्षण तथा मिट्टी परीक्षण कार्ड वितरण कार्य, कृशि विभाग जारी रखेगा। इस वर्श जारी किए गए 1 लाख मिट्टी परीक्षण कार्डों के अतिरिक्त आगामी वर्श में 1.25 लाख मिट्टी परीक्षण कार्ड जारी किए जाएंगे। मिट्टी परीक्षण प्रयोगषालाओं को भी आधुनिक उपकरण प्रदान करके सुदृढ़ किया जाएगा। कृशि तथा बागवानी विभागों द्वारा जैविक कृशि तथा केंचुआ खाद के प्रयोग को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अगले वर्श 1.50 लाख केंचुआ खाद इकाईयां स्थापित की जाएंगी तथा आगामी दो वर्शों में हमारी सरकार प्रत्येक फार्म हाऊस में केंचुआ खाद गड्डों का निर्माण सुनिष्चित करेगी।

15ण हिमाचल प्रदेष में दूध उत्पादन कुल 9 लाख टन अनुमानित है। पषुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान, संकर नसल तथा बेहतर पषुचारे की आपूर्ति से दूध के उत्पादन में वृद्धि करेगा। पिछले बजट भाशण में दूध उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए मैंने दूध के क्रय मूल्य में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी। मार्च 2009 से हमने इन दरों में 2 रुपये प्रति लीटर की और वृद्धि की है। आगामी वर्श में मिल्कफैड को 9.5 करोड़

रुपये की विषेश बजट सहायता मिलेगी। मिल्कफैड दूध उत्पादकों को हर पखवाड़े में अदायगी सुनिषिचित करेगा। मिल्कफैड तथा पषुपालन विभाग, प्राप्त दूध की गुणवत्ता में 'मोबाइल चिल्ड ट्रांसपोर्ट यूनिटस' के माध्यम से सुधार लाने हेतु कार्य करेंगे। मिल्कफैड ज़्यादा से ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी दूध समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास तथा सहकारिता विभाग के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा। पषुपालन विभाग दूध उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त पशुचारे की उपलब्धता सुनिष्चित करेगा। इस के लिए अगले वर्श 75 लाख रुपये की लागत से हमीरपुर में एक चारा विधायन संयत्र स्थापित किया जाएगा। युक्तिकरण प्रक्रिया द्वारा 25 पशुपालन संस्थाओं में से 21 को पशुपालन चिकित्सालायों तथा 4 को केन्द्रीय पशुपालन औशधालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया से 19 नई पशुपालन संस्थाएं भी खोली गई हैं।

16ण आगामी वर्श में मत्स्य विभाग आधुनिक मछली पालन तथा विपणन तकनीक से जीवनयापन गतिविधियों का तेज़ी से विस्तार करेगा। विभाग बेरोज़गार युवाओं को मछली पालन, मोती उत्पादन तथा व्यावसायिक ट्राउट पालन जैसी जल–आधारित गतिविधियों में प्रषिक्षित करेगा। मछली बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए मछली बीज फार्मों का विस्तार तथा नए फार्मों का निमार्ण किया जाएगा।

17ण हमारी सरकार नगदी फसलों, जैसे टमाटर, आलू, सेब, आम इत्यादि के लिए बीमा योजना आरम्भ करने के लिए वचनबद्ध है। 2009–10 में ऐसी प्रायोगिक बीमा योजनाएं आरम्भ की जाएंगी। हमने सोलन ज़िले में टमाटर तथा कांगड़ा और ऊना ज़िलों में रबी आलू की

फसल हेतु मौसम पर आधारित बीमा योजनाएं आरम्भ करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

18ण अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रयासों से किसानों को रोज़गार के बेहतर अवसर

उपलब्ध करवाने तथा उनकी आय बढ़ाने हेतु हमारी सरकार की वचनबद्धता से इस मान्य सदन के सभी माननीय सदस्य आष्वस्त होंगे। इस उद्देष्य से आगामी वर्श में कृशि तथा सम्बन्धित क्षेत्र, जिसमें सिंचाई सेवाएं भी षामिल हैं, के लिए मैंने 521 करोड़ रुपये के कुल योजना प्रावधान का प्रस्ताव रखा है। यह 2009–10 की कुल योजना प्रावधान का लगभग पॉचवा हिस्सा है।

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज

19ण ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए आगामी वित्त वर्श में मैंने 143 करोड़ रुपये का और प्रावधान किया है। अगले वित्त वर्श ''नरेगा'' के कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़ कार्य दिवसों से अधिक का रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग पूरी तरह तैयार है। अतः पंचायती राज संस्थाएं न केवल प्रत्येक घर को रोज़गार प्रदान करने अपितु ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना में भी बड़े पैमाने पर सुधार करने की स्थिति में है।

20ण मुझे यह घोशित करते हुए प्रसन्नता है कि पंचायत सहायकों के प्रोत्साहन के लिए उनकी 8 वर्श की संतोशजनक सेवा उपरान्त उन्हें पंचायत सचिव पदनामित किया जायेगा। हमारी सरकार ने सभी ग्राम रोज़गार सेवकों तथा तकनीकी सहायकों का न्यूनतम सेवा षुल्क क्रमषः 1500 रुपये व 2500 रुपये प्रतिमाह सुनिष्चित करने का निर्णय लिया है।

21ण हमारी सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी में 33 प्रतिषत की वृद्धि कर इसे 75 रुपये से 100 रुपये किया था। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण बेरोज़गारों द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्भावित वार्शिक मज़दूरी 7500 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गयी। यह घोशित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि अगले वित्त वर्श में हमारी सरकार कृशि न्यूनतम मज़दूरी में 10 प्रतिषत की और वृद्धि करेगी। इससे हमारे ग्रामीण परिवार प्रतिवर्श 11,000 रुपये की आमदनी अर्जित कर पायेंगे।

22ण हमारी सरकार गरीबों की आवासीय आवष्यकताओं के प्रति अत्याधिक चिंतित है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि ''इंदिरा आवास

योजना'' तथा ''अटल आवास योजना'' के अन्तर्गत विषेश बजट प्रावधान के परिणामस्वरूप आगामी वित्त वर्श में ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग, लगभग 9000 नए मकानों के निर्माण तथा 900 पुराने मकानों की मुरम्मत के लिए सहायता प्रदान करेंगे। इससे हमारी ग्रामीण जनता तथा अनुसूचित जाति के परिवार बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।

23ण ''संपूर्ण स्वच्छता अभियान'' के अन्तर्गत हमने मार्च 2010 तक सभी पंचायतों को 'खुले में षौच मुक्त' करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग तथा षिक्षा विभाग, सभी विद्यालयों में

छात्राओं के लिए 100 प्रतिषत षौचालय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे।

ऊर्जा

24ण अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हिमाचल का आर्थिक भविश्य प्रदेष के 20,564 मैगावाट जल–विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन पर निर्भर है। वर्तमान वित्त वर्श में हमारी सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं के निविदा मापदण्डों में बदलाव किया है। अतः 12 प्रतिषत, 18 प्रतिषत तथा 30 प्रतिषत निःषुल्क बिजली 'रॉयल्टी' प्राप्ति के बजाए, अब बिजली उत्पादक 12 से 26 प्रतिषत तक अतिरिक्त निःषुल्क बिजली 'रॉयल्टी' अदा करेंगे। अर्थात, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के आधार पर निजी क्षेत्र के अनेक बिजली उत्पादक राज्य सरकार को निषुल्क बिजली प्रदान करेंगे, जिसकी दर पहले 12 वर्शों में उत्पादित बिजली का 24 से 38 प्रतिषत, अगले 18 वर्शों में 30 से 44 प्रतिषत तथा परियोजना के अन्तिम 10 वर्शों में 42 से 56 प्रतिषत होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने 20 लाख रूपये प्रति मैगावाट की दर से 'अपफ्रंट प्रिमीयम' भी लिया है, जिससे चालू वित्त वर्श में सरकार को 600 करोड़ रुपये से भी अधिक आय होने की आषा है। इस प्रकार, हमने न केवल चालू वित्त वर्श में अतिरिक्त आर्थिक संसाधन

जुटाए हैं, बल्कि अगले 50 वर्शों से भी ज़्यादा अवधि के लिए हिमाचल प्रदेष के वित्तीय हितों की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई यह पारदर्षी स्पर्धात्मक

निविदा पद्धति सुषासन तथा वित्तीय विवेक के प्रति हमारी सरकार की वचनबद्धता का प्रतीक है।

25ण पर्यावरण रक्षा, ऊर्जा बचत और राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने की हमारी वचनबद्धता के दृश्टिगत सरकार ने इसी वित्त वर्श में ''अटल बिजली बचत योजना'' प्रारम्भ की है। लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से हमने राज्य के प्रत्येक घर को 4 'सी0एफ0एल0 बल्ब' मुफ्त वितरित किए हैं।

26ण वर्तमान वित्त वर्श में हमारी सरकार ने 'एषियन डवैल्पमैन्ट बैंक' से 4000 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज प्राप्त किया है। जिससे हिमाचल प्रदेष विद्युत परिशद् 800 मैगावाट से अधिक की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करेगा। 'ए0डी0बी0' से प्राप्त वित्तीय सहायता का 90 प्रतिषत प्रदेष सरकार को सीधे अनुदान के रूप में मिलेगी। यह हमारे प्रदेष की भावी समृद्धि के सषक्तिकरण हेतु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक है। लगभग 1000 मैगावाट की कुल क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेष ऊर्जा निगम को सौंपी गई हैं। इनमें से 5 परियोजनाओं के प्रमुख घटकों पर आगामी वित्त वर्श में कार्य आरम्भ हो जाएगा। ये परियोजनाएं सम्भवतः 2013 तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिससे राज्य सरकार को 1800 करोड़ रुपये की वार्शिक आमदनी होगी।

27ण हमारी सरकार ने तैयार बिजली के संग्रहण तथा संचारण को सुदृढ़ करने के लिए 27 अगस्त, 2008 को एक अलग संचारण निगम का भी गठन किया है। निगम ऊर्जा संग्रहण तथा संचारण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लगभग 4500 करोड़ रुपये का एक विस्तृत 'मास्टर प्लान' तैयार कर

रहा है। इन संचारण परियोजनाओं के लिए बाह्य वित्त पोशण तथा आर0ई0सी0;त्म्ब्द्ध और नाबार्ड से ऋण प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है।

28ण हमने हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत निगम की निर्माणाधीन 100 मैगावाट ऊहल जल विद्युत परियोजना को गति प्रदान की है, जो 2010 के अन्त तक तैयार हो जाएगी। हमारी सरकार ने हिमऊर्जा की माली हालत सुदृढ़ करने के लिए 5 मैगावाट से कम क्षमता वाली कुछ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को इस संगठन के लिए आरक्षित रखने की पहल की है। इस प्रकार लगभग 100 मैगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं हिमऊर्जा के स्वामित्व में हो जाएंगी, जिससे हिमऊर्जा प्रतिवर्श 150 करोड़ रूपये से भी ज़्यादा के आन्तरिक संसाधन जुटा पायेगा।

29ण ऊर्जा क्षेत्र के लिए रेखांकित सभी उपायों को सहायता प्रदान करने के लिए आगामी वित्त वर्श में मैं 355 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ, जो अगले वित्त वर्श के योजना परिव्यय का 13 प्रतिषत है।

सड़कें व सड़क परिवहन

30ण अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के साथ वार्शिक योजना पर विचार विमर्ष दौरान यह मुद्दा बार–बार उठा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के प्रयासों में तीव्रता लाई जाए और इस वित्त वर्श में अभूतपूर्व वर्शा तथा भू–स्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क नेटवर्क तुरंत ठीक किया जाए।

31ण रेल परिवहन के अभाव में सड़कें प्रदेष की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। सड़कों की बहाली तथा मुरम्मत कार्यों के लिए विषेश पैकेज प्रदान करने हेतु हम केन्द्र सरकार से बार–बार अनुरोध करते रहे हैं। यह अफसोसजनक है कि केन्द्र सरकार ने हमारे निवेदनों के महत्त्व को पूरी तरह नहीं समझा।

32ण उपरोक्त तथ्य के दृश्टिगत तथा गहन विचार विमर्ष के पषचात्, हमारी सरकार ने अगले वित्त वर्श में सड़कों को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इस मान्य सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि

सड़कों के लिए इस वित्त वर्श के 304 करोड़ के
मुकाबले, हमने 176 करोड़ की वृद्धि कर 2009–10 में 480 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया है। यह अगले वित्त वर्श में सड़कों और पुलों के लिए 58 प्रतिषत की वृद्धि है। परिवहन क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय पूर्ण योजना आकार का 20 प्रतिषत से भी अधिक है। परिव्यय में यह वृद्धि चालू विष्व बैंक सड़क परियोजना, माननीय विधायकों की 'आर0आई0डी0एफ0' प्राथमिकताओं तथा विद्यमान

सड़क नेटवर्क के रख–रखाव की आवष्कताओं को पूरा करने हेतु की गई है।

33ण राश्ट्रीय मापदण्डों की तुलना में हिमाचल प्रदेष में सड़कों की सघनता राश्ट्रीय औसत से लगभग आधी है। हमारे लगभग 50 प्रतिषत गांव अभी भी सड़कों से जोड़े जाने हैं। मुझे विष्वास है कि सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हमें सड़क नेटवर्क निर्माण तथा रख–रखाव को न केवल अगली वार्शिक योजना में अपितु सालों–साल प्राथमिकता देनी होगी। आगामी वर्श में 500 से ऊपर जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। ''प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना'' के अन्तर्गत हमने 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 310 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, 822 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 221 परियोजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी हैं। हमारी सरकार ने वर्श 2012 तक 250 से अधिक की जनसंख्या के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

34ण सड़क नेटवर्क विस्तार के साथ–साथ जनता की लगातार मांग रही है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में विस्तार किया जाए। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेष को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने एक नयी योजना लागू की है। हमने बेरोज़गार युवाओं को

पथकर अदायगी बिना, ग्रामीण सड़कों पर बस तथा छोटी 'मैक्सी कैब' गाड़ियां चलाने की अनुमति दी है। हमारी सरकार का इरादा है कि नज़दीकी खण्ड मुख्यालयों/'नोटिफाईड एरिया कमेटियों' को गांव से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों की रूट परमिट आबंटन प्रक्रिया को और उदार बनाया जाए। इस प्रकार हम 'हब तथा स्पोक ट्रांस्पोरटेषन मॉडल' प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे सभी गांवों और षहरों के बीच पर्याप्त परिवहन सेवाओं के लिए निजी–सार्वजनिक सहभागिता बढ़े। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु हमारी सरकार ने ग्रामीण सड़कों पर सभी 'बस रूट' के लिए पथकर में छूट देने का निर्णय लिया है।

35ण हिमाचल पथ परिवहन निगम हेतु अगले वित्त वर्श में 43 करोड़ रुपये की योजना सहायता की घोशणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह वर्तमान वित्त वर्श के प्रावधान से 30 प्रतिषत की वृद्धि है और इससे हिमाचल पथ परिवहन निगम 300 पुरानी बसें बदलेगा। सड़क सुरक्षा की दृश्टि से अगले वर्श जसूर में एक 'ड्राईविंग स्कूल' आरम्भ किया जाएगा। अगस्त, 2009 तक षिमला का अन्तर्राज्य बस अड्डा चालू कर दिया जाएगा तथा अर्की, आनी, सुन्दरनगर और जुब्बल के बस अड्डों का निर्माण कार्य भी अगले वर्श के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

36ण हिमाचल पथ परिवहन निगम को अगले वित्त वर्श में सम्भावित वेतनमान संषोधन दायित्वों का सामना करना होगा। इसके लिए मैंने इस वर्श के 48 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्श में 60 करोड़ रुपये की गैर योजना सहायता का प्रावधान किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम हेतु अगले वर्श लगभग 120 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। जिसमें पिछले ऋण दायित्वों की अदायगी भी षामिल है।

जलापूर्ति

37ण अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी सरकार की हमेषा उच्च प्राथमिकता रही है। मैंने पिछले बजट में ग्रामीण जलापूर्ति परिव्यय में 40 प्रतिषत की वृद्धि की थी। इससे

पेयजल आपूर्ति में तेज़ी आई तथा लम्बे समय से अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने में हमें मदद मिली। हमारी पहल से 2000 हैंडपम्प, विषेशकर राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित हुए, जिसको प्रदेष की जनता तथा जन–प्रतिनिधियों ने सराहा है। इन सभी प्रयासों को जारी रखने हेतु आगामी वर्श में हमारी सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

38ण वार्शिक योजना पर चर्चा के अनुरूप अगले वर्श सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग चालू योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देगा। नये खर्चों के अन्तर्गत हमारी सरकार ग्रेवटी पेय जलापूर्ति योजनाओं, टयूबवैल तथा हैन्डपम्पों के निर्माण पर बल देती रहेगी। इस वर्श के अन्त तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17,463 हैण्डपम्प स्थापित किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्श के अन्त तक राज्य में स्थापित कुल हैण्डपम्पों की संख्या लगभग 20,000 हो जाए। अगले वर्श में हम 172 करोड़ रुपये की सकल लागत से तीन मुख्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं भी आरम्भ करेंगे। इनसे बिलासपुर तथा कांगड़ा ज़िलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों की 1171 बस्तियां लाभान्वित होंगी।

39ण राजधानी क्षेत्र षिमला के लिए योजना आयोग तथा षहरी विकास मन्त्रालय ने पब्बर नदी ग्रेवटी जलापूर्ति योजना को बाह्य वित्त पोशण के लिए संस्तुत किया

है। हमारी सरकार इस मामले पर ज़ोरदार अनुवर्ती कारवाई कर रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

40ण सभी माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले बजट में हमने अनुसूचित जाति उप–योजना को 231 करोड़ से बढ़ाकर 594 करोड़ रुपये किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 2009–10 की योजना में इस राषि में 74 करोड़ की और वृद्धि करके कुल 668 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना प्रावधान से राज्य के सभी अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित होंगे तथा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में

चालू पूंजीगत कार्यों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ेगी।

41ण अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यगण जानते हैं कि हमारी सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। इस उद्देष्य से सत्ता सम्भालते ही हमने वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों की पेन्षन राषि में 50 प्रतिषत की वृद्धि कर इसे 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिमास कर दिया था। पहली जनवरी 2009 से हमने इस पेन्षन राषि में 10 प्रतिषत की और वृद्धि कर इसे 330 रुपये प्रतिमास कर दिया है। मेरे पिछले बजट आष्वासन के अनुरूप हमने गरीबी रेखा से नीचे सभी पात्र व्यक्तियों को प्रथम अप्रैल, 2008 से सामाजिक पेन्षन नेटवर्क में षामिल कर लिया है। इस प्रकार हमने लगभग 15,000 परिवारों को सामाजिक पेन्षन नेटवर्क में जोड़ा है। करीब 2.52 लाख परिवार अब सामाजिक सुरक्षा पेन्षन प्राप्त कर रहे हैं, जो राज्य के हर पांच परिवारों में लगभग एक परिवार बनता है। हमारी सरकार अगले कुछ वर्शों में चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेन्षन को 400 रुपये प्रतिमास करने के लिए वचनबद्ध है।

42ण मैंने पिछले वर्श ''मातृषक्ति बीमा योजना'' के अन्तर्गत बीमा लाभों को दुगुना करके दुर्घटना में मृत्यु पर 50,000 रुपये व एक अंग की क्षति पर 25,000 रुपये किया था। समाज के सबसे गरीब तबके के प्रति हमारी वचनबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, इन बीमा लाभों को फिर से दुगुना करके, दुर्घटना में मृत्यु पर 1 लाख रुपये तथा एक अंग की क्षति पर 50,000 रुपये किया गया है।

जनजातीय विकास

43ण जनजातीय क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार पर पूर्ण भरोसा जताया है। तत्कालीन प्रधानमन्त्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर रोहतांग सुरंग निर्माण परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह सुरंग लाहौल तथा पांगी क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा होगी। इस पहल को आगे बढ़ाने हेतु पिछली कांग्रेस सरकार ने केन्द्र

सरकार के साथ कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, और इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण कार्य को आरम्भ करने में 5 बहुमूल्य वर्श ज़ाया हो गए। इस सुरंग के निर्माण कार्य को तेज़ी से आरम्भ करने का मामला हमारी सरकार केन्द्रीय रक्षा मन्त्रालय तथा सीमा सड़क संगठन के साथ लगातार उठा रही है। हमारे निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप सुरंग के निमार्ण की निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। अगले वित्त वर्श में जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत जनजातीय कल्याण हेतु 243 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा तथा तकनीकी षिक्षा

44ण षिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान षैक्षणिक ढ़ांचे को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक स्तर पर षिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। इस उद्देष्य से हमने अपनी सरकार की ''ग्रामीण विद्या उपासक योजना'' को फिर से आरम्भ करने का निर्णय लिया है। पंचायतों को नए प्राथमिक पाठषाला अध्यापक लगाने के लिए पर्याप्त अनुदान दिया जाएगा। हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए सभी पात्र ग्रामीण विद्या उपासक, 1 अप्रैल, 2009 से अनुबन्ध श्रठज अध्यापक बन जाएंगे।

45ण राज्य में सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पाठषालाओं को राश्ट्रव्यापी 'एन0सी0ई0आर0टी0' ;छब्म्त्ज्द्ध पाठ्यक्रम पद्धति अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस से षिक्षा के मानक में एकरूपता आयेगी तथा कर्मचारियों को उनके स्थानान्तरण पर अपने बच्चों को नई पाठषालाओं में दाखिल करने मे भी आसानी रहेगी।

46ण अंग्रेजी भाशा कौषल, 'आई0टी0' षिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास षिक्षित युवाओं के लिए बेहतर रोज़गार अवसरों की कुंजी है। इसलिए षिक्षा विभाग महाविद्यालय तथा विद्यालय स्तरों पर ऐसे कौषल विकास के लिए विषेश नीति तैयार करेगा।

47ण सरकार निजी विष्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में तीन निजी विष्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। कम से कम 6–7

इसी प्रकार के और विष्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इस उद्देष्य से सार्वजनिक–निजी सांझेदारी द्वारा ''अटल षिक्षा कुंज'' नामक एक षैक्षणिक 'हब' बद्दी में 62 करोड़ की अनुमानित लागत से 554 बीघा ज़मीन पर बनाया जा रहा है। अगले वित्त वर्श में हमारी सरकार प्रत्येक ज़िले में भूमि बैंक चिह्नित करेगी जिन्हें ख्याति प्राप्त निजी विष्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उपलब्ध करवाया जा सके। इस प्रक्रिया से हम स्नातकों के लिए रोजगार की सम्भावनायें बढ़ाने का इरादा रखते हैं। वर्तमान बी0एड0 कॉलेजों को ज़्यादा तकनीकी पाटय्क्रमों के माध्यम से रोज़गार–परक प्रषिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

48ण हमारी सरकार मण्ड़ी में एक 'आई0आई0टी0', कांगड़ा में एक केन्द्रीय विष्वविद्यालय व एक 'राश्ट्रीय फैषन टैक्नोलोजी' संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार की सांझेदारी प्राप्त करने में सफल हुई है। हिमाचल प्रदेष में एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (प्ण्ड) तथा एक भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (प्ण्प्ज) खोलने के मामले पर हम केन्द्रीय सरकार के साथ अनुवर्ती कारवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेष के प्रत्येक ज़िले में एक 'कॉलेज ऑफ एक्सीलैन्स' खोलने हेतु विषेश धन राषि प्रदान करने का मामला भी केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा। ज़िला सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल स्पिति में चरणबद्ध तरीके से 5 बहुतकनीकी संस्थान खोले जाएंगे।

49ण हमारी सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय की सहभागिता से बिलासपुर में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु केन्द्र सरकार को सहमत किया है, जिसमें विषेश रूप से जलविद्युत परियोजनाओं संबंधी षिक्षा प्रदान की जायेगी। मण्ड़ी, ऊना, सोलन तथा हमीरपुर ज़िलों में मैडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु सार्वजनिक–निजी

सांझेदारियां निश्पादित की जा रही हैं। निजी नर्सिंग कॉलजों तथा संस्थाओं को स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।

50ण उच्च षिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिषत की राश्ट्रीय औसत दाखिला दर के मुकाबले हिमाचल प्रदेष 20 प्रतिषत से अधिक की उच्चतम दाखिला दर प्राप्त कर चुका है। प्रदेष सरकार भविश्य में अधिकाधिक सार्वजनिक–निजी भागीदारी द्वारा इस दाखिला दर को लगभग 50 प्रतिषत तक बढ़ाने का प्रयास करेगी ताकि हिमाचल प्रदेष को देष का अग्रणी षिक्षा हब बनाया जाए।

स्वास्थ्य एवं आयुर्वैद

51ण अध्यक्ष महोदय, सरकार अगले वित्त वर्श के दौरान प्रदेष की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार करेगी। हम चिकित्सकों तथा पैरामैडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हर सम्भव कदम उठा रहे हैं। इस वर्श रोगी कल्याण समितियों की संख्या दुगुनी से अधिक होकर 235 से 485 हो गयी है, जो राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं की कुल संख्या के 80 प्रतिषत से भी अधिक है। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से भी संस्थाविषेश आधार पर डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। इस वर्श, आज तक 225 डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त 175 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरा जा रहा है। नर्सों के 262 पद भरे जा चुके हैं तथा पैरा मेडिकल स्टॉफ की षेश रिक्तियों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 300 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एक वर्श का प्रषिक्षण कोर्स करवाने की प्रक्रिया भी जारी है।

52ण डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृश्टिगत हमारी सरकार आई0जी0एम0सी0 षिमला में एम0बी0बी0एस0 सीटों को 65 से 100 तक बढ़वाने के लिए आवष्यक कदम उठाएगी। विषेशज्ञों की कमी को पूरा करने हेतु टाण्डा मेडिकल कॉलेज और आई0जी0एम0सी0 षिमला में 20 'पोस्ट ग्रेजुएट' सीटों में वृद्धि करवाई जा रही है। 2010 तक इन मेडिकल कॉलेजों में 'पोस्ट ग्रेज्यूएट' सीटों की संख्या 83 हो जाएगी।

53ण डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए, सोलन तथा पालमपुर में निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम

के माध्यम से मण्डी में भी एक 'मल्टी स्पेषिएलिटी' अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जहां पर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक–निजी सांझेदारी से ऊना, मण्डी तथा हमीरपुर में और मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार है। जिसके लिए करारनामें तैयार करने हेतु हमारी सरकार ने 'कनसलटेन्ट्स' नियुक्त किए हैं।

54ण नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए आगामी वित्त वर्श के दौरान निजी क्षेत्र में हम 12 बी0एस0सी नर्सिंग कॉलेज तथा 28 नर्सिंग स्कूल खोलने की आषा करते हैं। बड़ू साहिब, ज़िला सिरमौर में इस वर्श निजी क्षेत्र में एक बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज खोला गया है।

55ण इन प्रयासों से हम सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रषिक्षित स्टॉफ की कमी को पूरा करेंगे। इससे षिक्षित युवाओं के लिए राश्ट्रीय तथा अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के रोज़गार अवसर भी खुलेंगे।

56ण हमारी सरकार आगामी वित्त वर्श में प्रदेष के सभी ज़िलों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों हेतु एक बृहद् स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ करेगी। सार्वजनिक–निजी सांझेदारी में हम बृहद् आपातकाल चिकित्सा तथा 'ऐम्बुलेन्स' सेवाएं आरम्भ करने की सम्भावनाएं भी तलाषेंगे।

57ण अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को वरिश्ठ नागरिकों की विषेश आवष्यकताओं के अनुरूप भी ढालना होगा । आयुर्वेद विभाग ने वरिश्ठ नागरिकों हेतु प्रत्येक मंगलवार को विषेश ओ0पी0डी0 सेवायें आरम्भ कर दी है। अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थाएं भी वरिश्ठ नागरिकों की विषेश स्वास्थ्य आवष्यकताओं को पूरा करेंगी।

58ण टाण्डा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को 'एम्स' ;।प्प्डैद्ध के बराबर स्तरोन्नत करने के लिए हम एक विषेश योजना आरम्भ करेंगे। इस उद्देष्य से, हमने इसी महीने भारत सरकार से 125 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त की है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, अगले वर्श, प्रसूति तथा षिषु सेवाओं को कमला नेहरू अस्पताल से

आई0जी0एम0सी0 में स्थानांतरित करने की सम्भावना भी तलाषी जाएगी।

पर्यटन

59ण पर्यटन आर्थिक विकास व रोज़गार उत्पन्न करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। 2009–10 में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटकों को आकर्शित करना हमारा लक्ष्य रहेगा। इस के लिए पर्यटन विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर सुनिष्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेष पर्यटन विकास निगम की तरह, कम से कम 70 प्रतिषत निजी होटल 'इंटरनेट वेबसाईट' पर सूचना तथा 'ऑन लाईन' आरक्षण सुविधाएं प्रदान करें।

60ण ग्राामीण ''होम स्टे पर्यटन योजना'' हमारी सरकार द्वारा आरम्भ की जा चुकी है। इस के अन्तर्गत 'हब एण्ड स्पोक' व्यवसाय पद्धति प्रोत्साहित की जाएगी जिसमें षिमला, मनाली, धर्मषाला, डलहौज़ी इत्यादि लोकप्रिय स्थलों में आये पर्यटकों को आसपास बसे धरोहर गांवों में ठहरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ''होम स्टे योजना'' के अन्तर्गत ऐसे स्थल–समूहों को सुसाध्य बनाने हेतु योजनाएं तैयार करेगा। पर्यटकों को पंचकर्म जैसी पर्यटन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग आयुर्वेद विभाग का सहयोग लेगा। वरिश्ठ नागरिकों के लिए हिमाचल प्रदेष पर्यटन विकास निगम विषेश 'इनोवेटिव टूरिज़म पैकेज' तैयार करेगा, जिसमे 'ऑफ सीज़न' छूट दी जाएगी।

61ण माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेष के अनेक सुन्दर स्थलों का उल्लेख किया गया था जिनमें पर्यटन की बहुत सम्भावनाएं हैं। अगले वर्श पर्यटन विभाग इन में से 5 सबसे अच्छे स्थलों को चिह्नित करेगा, जिनका नये पर्यटक स्थलों के रूप में विकास तथा विपणन किया जा सके।

62ण पिछले बजट भाशण में मैंने इस मान्य सदन को सूचित किया था कि हमारी सरकार प्रदेष में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बाह्य वित्त पोशित परियोजना पर कार्य कर रही है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्श हो रहा है कि इस दिषा में पर्याप्त प्रगति हुई है और 'एषियन

डवैल्पमैन्ट बैंक' ने प्रदेष में पर्यटन विकास के लिए धन उपलब्ध करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। हमारी सरकार ने 350 करोड़ रुपये से अधिक की ढांचागत परियोजनाएं 'ए0डी0बी0' को वित्तीय सहायता हेतु भेजी हैं, जो 90 प्रतिषत अनुदान के आधार पर आएंगी। हमीरपुर में एक नया भारतीय होटल प्रबन्धन संस्थान तथा धर्मषाला में 'फूडक्राफ्ट इंस्टीच्यूट' स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इन संस्थानों के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की राषि स्वीकृत की गई है। ये संस्थान आतिथ्य क्षेत्र में रोज़गार प्राप्ति हेतु प्रतिवर्श 400 युवाओं को प्रषिक्षित करेंगे।

63ण हिमाचल प्रदेष के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक पर्यटन लोकप्रिय रहा है। धार्मिक पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने तथा उन्हें मंदिरों के आसपास पर्यटक स्थलों की ओर आकर्शित करने हेतु सम्बन्धित मंदिर प्रबन्धन समितियों के साथ विषेश नीति तैयार की जाएगी। परिवहन व पर्यटन विभाग प्रदेष के अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों में रेडियो तथा 'यूज़र फ्रेन्डली' मीटर युक्त टैक्सी सेवाएं आरम्भ करेंगे।

वन, वन्य प्राणी एवं पर्यावरण

64ण हमारी सरकार 'इको–टूरीज़म' को वन विभाग तथा पर्यटन विभाग के बेहतर तालमेल से बढ़ावा देने हेतु हर सम्भव कदम उठा रही है। इस वर्श राज्य वन निगम को 'इको–टूरीज़म' प्रोत्साहन संबंधी अतिरिक्त विकासात्मक एवं व्यावसायिक कार्य सौंपा गया है। इस वर्श 5 'इको–टूरीज़म सर्किटस' विकसित किए गए हैं तथा वन विभाग व राज्य वन निगम ऐसे और स्थलों को चिह्नित करेगा। लगभग 100 सरल तथा दुर्गम 'ट्रैकिंग' मार्ग चिह्नित किए जाएंगे जिनका प्रचार–प्रसार तथा दोहन टूर आपरेटरों तथा पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेष पर्यटन विकास निगम, वन विभाग व युवा सेवायें

एवं खेल विभाग की मइेपजमे के माध्यम से किया जाएगा।

65ण पर्यावरण सुरक्षा व पर्यटन सम्भावनाओं के विकास के बीच एक पारस्परिक संबन्ध है। पर्यावरण विभाग ने राज्य के लिए विस्तृत 'पर्यावरण मास्टर प्लान' तैयार करने हेतु एक 'कन्सलटेन्ट' नियुक्त किया है। यह प्लान सितम्बर, 2009 तक तैयार हो जायेगा। इसके उपरान्त हम 'एनवायरनमेन्ट फ्रेन्डली' कार्य योजना लागू करने हेतु नीतिगत कदम उठाएंगे।

66ण हमारी सरकार प्रदेष में पर्यावरण संरक्षण एवं सत्त विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेष को देष का पहला कार्बन–रहित राज्य बनाने के लिए पर्यावरण विभाग पहल कर चुका है। इस विष्वास के साथ कि किसी भी योजना में आम जनता की भागीदारी होना बहुत महत्तवपूर्ण है, पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेष में ''सामुदायिक पर्यावरण निर्धारण, जागृति, पक्ष समर्थन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन न्यूट्रेलिटी'' कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रदेष में विभिन्न स्तरों पर गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, पर्यावरण सभाओं, महिला मण्डलों तथा पंचायत स्तर के सभी सामुदायिक केन्द्रों व अन्य धारकों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जाएगा। यह स्वैच्छिक भावना से परिपूर्ण प्रयास होगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कोस्टा–रीका ;ब्वेजं त्पबंद्ध देष के बाद, हिमाचल प्रदेष सरकार विष्व की दूसरी ऐसी सरकार है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन न्यूट्रेलिटी की दिषा में सत्त प्रयास कर रही है। हाल ही में ज्म्त्प् ;जीम म्दमतहल ंदक त्मेवनतबमे प्देजपजनजमद्ध द्वारा आयोजित षिखर सम्मेलन में विष्व समुदाय द्वारा भी हिमाचल के इन प्रयासों को सराहा गया। हमारी सरकार द्वारा वायु तथा जल प्रदूशण, ठोस कचरा तथा मल–निकास प्रबन्धन, सड़कों तथा जल विद्युत परियोजनाओं के मलबे का निपटान, कूड़े–कचरे की 'रि–साईक्लिंग','बायोमैडिकल वेस्ट' इत्यादि महत्त्वपूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी मामलों का निवारण किया जा रहा है।

67ण सतलुज नदी घाटी में 4 जल विद्युत परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में तेज़ी से सुधार करने हेतु, विष्व बैंक विकास नीति सहायता के आधार पर,

अगले वर्श 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस समय वन विभाग द्वारा 21 'कैट प्लान' चलाए जा रहे हैं। अगले वर्श में व्यापक पौध रोपण तथा भू–संरक्षण गतिविधियों के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक राषि का विषेश प्रावधान किया गया है।

68ण हमारे प्रदेष में 6000 वर्ग किलोमीटर ऐसी वन भूमि है जिस पर पर्याप्त मात्रा में वन नहीं है। आगामी वर्श के दौरान ऐसी भूमि पर गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि की सांझेदारी से वन विभाग अधिक से अधिक वानिकी गतिविधियां चलाएगा। इस सांझेदारी से 'कार्बन क्रैडिट' अर्जित किए जा सकेंगे।

उद्योग

69ण अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा पिछले षासनकाल के दौरान जनवरी, 2003 में उद्योगों के लिए घोशित विषेश प्रोत्साहन पैकेज के फलस्वरूप, हिमाचल प्रदेष में औद्योगिक विकास को गति मिली। वर्तमान यू0पी0ए0 सरकार ने इसकी अवधि को मार्च, 2007 तक घटाया और फिर इसे मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया। इस सर्वव्यापक मंदी के दौर में केन्द्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज घोशित कर रही है। हमारे पैकेज की अवधि को मूल तिथि, 2013 तक किया जाना अब अपरिहार्य हो गया है। हम केन्द्र सरकार से इसी आधार पर पुनः विचार करने का अनुरोध कर चुके हैं।

70ण राहत पैकेज के साथ–साथ उचित औद्योगिक आधारभूत ढांचा होना भी आवष्यक है। हमारी सरकार के प्रयासों से उद्योगों के लिए इस वर्श षरद् ऋतु में बिजली की कोई कमी नहीं हुई है। हमने चमां सवंक ीवनते में भी बिजली आपूर्ति पर पाबन्दी नहीं लगायी। यह सुनिष्चित ऊर्जा आपूर्ति हिमाचल प्रदेष में स्थित उद्योगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, जबकि पड़ोसी राज्य बिजली की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

71ण औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए भी बेहतर प्रयास किए गए हैं। वर्तमान वर्श में औद्योगिक महत्त्व की सड़कों में सुधार के

उद्देष्य से लोक निर्माण विभाग के लिए 5 करोड़ रुपये का विषेश प्रावधान किया गया था। हमारी सरकार आगामी वर्श में भी इस कार्यक्रम पर अधिक बल देगी। इसी वर्श बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ विकास प्राधिकरण के लिए औद्योगिक आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु 5 करोड़ रुपये के विषेश अनुदान का प्रावधान किया गया है। आवासीय कमी के दृश्टिगत हिमुडा इस वर्श बद्दी, नालागढ़ और परवाणु में 1116 फ्लेटों का निर्माण पूरा करेगा। संस्थागत आधारभूत ढॉचे में सुधार लाने के लिए, इस साल हमने बद्दी में अलग से एक पुलिस ज़िला तथा एक लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बनाया है। यहां हमने अलग से एक तहसील, एक श्रम तथा एक 'ड्रग लाईसेसिंग' प्राधिकरण कार्यालय भी खोले हैं। औधिगिक आधारभूत ढ़ांचे में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण के साथ, विषेशतः औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, गैस 'पाईपलाईन' बिछाने हेतु एक करारनामा भी हस्ताक्षरित किया है। इसके द्वारा सी0एन0जी ;ब्छळद्ध परिवहन ईंधन व औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी।

72ण हमारी सरकार, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर सड़कों से ज़ोड़ने के लिए, पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। बद्दी–सिसवां–चण्डीगढ़ सड़क 2009 में चालू हो जायेगी। हमने पंजाब सरकार के साथ 'ग्रेटर मोहाली एक्सप्रैस मार्ग' के निमार्ण का एक सांझा कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है। यह मार्ग मोहाली में बनाये जा रहे अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अड्डे से बद्दी को जोड़ेगा। हमारी सरकार पथ परिवहन तथा राश्ट्रीय उच्च मार्ग मन्त्रालय पर ज़ोर डालेगी, कि वह चण्डीगढ़–पिंजौर 4 लेन मार्ग को षीघ्र पूरा करे तथा पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राश्ट्रीय उच्च मार्ग को 4 लेन बनाने का कार्य आरम्भ करे। इसी प्रकार, चण्डीगढ़–बद्दी, भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी तथा नंगल–तलवाड़ा 'ब्रॉडगेज' रेल लाइनों के कार्यों में तेज़ी लाने हेतु रेल

मंत्रालय पर भी ज़ोर डाला जा रहा है। मनाली तथा लेह तक रेल लाइन के लिए हमारी सरकार द्वारा थ्मेंपइपसपजल `जनकपमे भी आरम्भ करवाई गई हैं।

73ण आगामी वर्श उद्योग विभाग द्वारा बद्दी में पुरूशों तथा महिलाओं के लिए कामगार होस्टल, व्यापार केन्द्र व 'कंटेनर कॉरपोरेषन ऑफ इंडिया' के माध्यम से 'इनलैंड कंटेनर डिपो' स्थापित करने का मामला आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार विभाग बद्दी–नालागढ़ क्षेत्र के लिए उनदपबपचंस `ूंजम जतमंजउमदज चसंदज तथा बद्दी–बरोटीवाला क्षेत्र के लिए `मूंहम ंदक बवउउवद मसिसिनमदज जतमंजउमदज चसंदज स्थापित करने पर अनुवर्ती कारवाई करेगा। इसके अतिरिक्त बद्दी में ट्रकों तथा अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने हेतु एक परिवहन नगर के निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब परियोजनाएं लगभग 200 करोड़ रुपये के सकल निवेष से सार्वजनिक–निजी सांझेदारी के माध्यम से चालू की जाएंगी।

74ण विकास की गति को तेज़ करने के उद्देष्य से हमारी सरकार ने एक भूमि बैंक बनाया है। लगभग 6000 बीघा सरकारी व निजी भूमि उद्योग स्थापित करने हेतु चिहि्नत की गई है। हमने औद्योगिक प्लॉट के हस्तान्तरण की षर्तों को उदार बनाया है ताकि अप्रयुक्त पड़ी भूमि का उत्पादनकारी प्रयोग हो सके। हमारी सरकार ने 'बायो टेक्नोलोजी' तथा सौर ऊर्जा के उभरते हुए क्षेत्रों को भी उद्योग घोशित किए जाने व इन्हें अन्य उद्योगों के समान राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।

75ण उद्योग विभाग माल व सेवाओं की उत्कृश्ट 'प्रोक्योरमैंट' प्रणाली विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्षी तथा प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार षीघ्र ही एक अधिनियम लाएगी।

गृह

76ण हिमाचल प्रदेष के लोग षान्तिप्रिय, ईमानदार तथा मेहनती हैं। प्रदेष का वातावरण ऐसा है, जिसमें सरकार अपनी पूरी षक्ति विकासात्मक गतिविधियों में लगाती है। परन्तु, बढ़ते हुए औद्योगीकरण व प्रवासी श्रमिकों के आगमन,पड़ोसी राज्यों तथा अन्तर्राश्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा मामलों के दृश्टिगत सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में ढील नहीं दे सकती। इसलिए हमारी सरकार ने राज्य तथा ज़िला स्तर पर राज्य पुलिस बल के अन्तर्गत त्वरित कार्रवाई दलों के गठन का निर्णय लिया है। गुप्तचर अनुभाग को भी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है। पुलिस बल की रिहायषी आवष्यकताओं को पूरा करने हेतु आगामी वर्श में 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

77ण अग्निषमन सेवाएं आपदा प्रबन्धन दौरान बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाती हैं। आगामी वर्श में मैंने आधुनिक 'फायर टेन्डरों' व अग्निषमन उपकरणों की खरीद हेतु 3 करोड़ रुपये के विषेश परिव्यय का प्रावधान भी किया है।

78ण न्यायपालिका की आवष्यकताओं के दृश्टिगत न्यायिक क्षेत्र में चालू संरचनात्मक कार्यों के लिए 19 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। सतर्कता विभाग को विषेश निर्देष दिए गए हैं कि भ्रश्टाचार के सभी मामलों के प्रति असहनीयता का रूख अपनाएं व ऐसे मामलों की पूर्ण जॉच निडरता तथा बिना पक्षपात से करें। यह सुषासन की दिषा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्वदअपबजपवद तंजमे में सुधार लाने के लिए अभियोजन विभाग द्वारा बेहतर प्रषिक्षण दिया जा रहा है।

राजस्व विभाग

79ण कुशल प्रषासन के लिए सही भू–अभिलेखों की उपलब्धता अत्याधिक महत्त्वपूर्ण है। राजस्व विभाग द्वारा सभी अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का विषेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी गांवों की 'डाटा ऐन्टरी' का काम पूरा किया जा चुका है तथा जून, 2009 तक सभी 113 कार्यरत तहसीलों

तथा उप तहसीलों के माध्यम से आम जनता को उनके भूमि अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां प्राप्त हो सकेंगी।

80ण हमारी सरकार ने निर्देष जारी किए है कि पटवारी सोमवार, बुधवार तथा षुक्रवार को प्रवास पर नहीं जाएंगे, ताकि वे आम जनता की सेवा के लिए अपने पटवारखाने में उपलब्ध रहें। इन निर्धारित दिनों की सूचना सम्बन्धित पटवारखाने में सार्वजनिक स्थान पर लगाई जायेगी। भू–राजस्व कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं बढ़ाने हेतु मैं अगले वर्श के बजट में 5.24 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहा हूँ।

षहरी विकास

81ण अगले वर्श षहरी विकास विभाग राश्ट्रीय षहरी नवीकरण मिषन के अन्तर्गत बुनियादी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विषेश बल देगा। इसमें षिमला, हमीरपुर, धर्मषाला तथा सोलन की आवासीय परियोजनाओं के साथ–साथ हमीरपुर, षिमला तथा मण्डी के लिए अन्य षहरी बुनियादी परियोजनाएं भी षामिल होंगी। पर्यटन परियोजनाओं के लिए 'ए0डी0बी0' से राषि प्राप्त करने हेतु षहरी विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग मिलकर कार्य करेगें। यह राषि 'कमर्षियल' पार्किंग सहित षहरी विकास योजनाओं पर व्यय की जाएगी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 षहरों में चलाई जा रही मल–निकासी योजनाओं को पूरा करने हेतु आगामी वर्श में 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं की कार्य गति के अनुरूप इन्हें और धन देने पर भी विचार किया जा सकता है। अगले वर्श में षहरी विकास के लिए 52 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

82ण सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा षिक्षा विभाग चरणबद्ध तरीके से सभी वरिश्ठ माध्यमिक पाठषालाओं को कम्प्यूटर प्रयोगषालाओं तथा 'ब्राडबैंड' से जोडेंगे। सरकारी व्यावसायिक संगठनों तथा सरकार के अधीन मन्दिरों के वित्त प्रबन्धन सुधारने के लिए उनकी लेखा प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी उचित मूल्य

दुकानों के स्तर तक कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल

83ण अध्यक्ष महोदय, मान्य सदन के सदस्यों को याद होगा कि मैंने पिछले बजट भाशण में आष्वासन दिया था कि धर्मषाला व हमीरपुर में 'सिंथैटिक ऐथेलैटिक ट्रैक्स' का निमार्ण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा आगामी वर्श में लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से यह निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। सभी पंचायतों तथा षिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों व महाविद्यालयों में अच्छे खेल मैदानों की सुविधाएं सुनिष्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रदेष के ज़िलों में 'हिमाचल प्रदेष क्रिकेट ऐसोसिएषन' की सांझेदारी से क्रिकेट स्टेडियमों का निमार्ण किया जाएगा। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के आहार भत्ते ;क्पमज डवदमलद्ध को राज्य के भीतर 60 रुपये से 80 रुपये प्रतिदिन तथा राज्य के बाहर 125 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के योजना बजट में 45 प्रतिषत वृद्धि करके इसे वर्तमान वर्श के 7.18 करोड़ के मुकाबले आगामी वर्श में 10.41 करोड़ रुपये किया है।

भाशा, कला एवं संस्कृति

84ण हिमाचल प्रदेष की कला एवं संस्कृति देष में अपनी एक अलग एवं विषिश्ट पहचान रखती है। भाशा, कला एवं संस्कृति विभाग कांगड़ा चित्रकला, चम्बा रूमाल, लकड़ी पर नक्काषी तथा मूर्ति कला जैसी अनूठी हिमाचली कला को बड़े पैमाने पर प्रदर्षित करने की दिषा में कार्य करेगा। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्वउउवदूमंसजी खेलों में प्रदेष की दस्तकारी तथा कला वस्तुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में रखने हेतु हमारी सरकार भरसक प्रयास करेगी। इससे भविश्य में देषी तथा विदेषी बाज़ारों में प्रदेष के हस्तषिल्प के विपणन प्रयासों को मदद मिलेगी।

85ण ज़िला कांगड़ा का मसरूर 'रॉक कट' मंदिर देष में इस षैली के मात्र 4 मंदिरों में से एक है । इस मंदिर को हमारी सरकार तथा भारतीय

पुरातात्विक सर्वेक्षण के सांझे प्रयासों से मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

86ण षिमला के 'गेयटी थियेटर' के जीर्णोद्धार का कार्य अगले वर्श पूरा कर लिया जाएगा और इसे एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एक भव्य प्रकाष व ध्वनि प्रदर्षन मुख्य पर्यटक आकर्शण के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिष राज सम्पदा, स्वतन्त्रता संघर्श तथा 1972 में हस्ताक्षरित भारत–पाक संधि तथा वार्ता सहित षिमला की समृद्ध धरोहर को दर्षाया जाएगा।

सैनिक कल्याण विभाग

87ण सषस्त्र सेना के प्रत्येक अभियान में हिमाचल प्रदेष के सैनिकों ने हमेषा बहादुरी की ऊंची मिसाल कायम की है। हमारी सरकार ने प्रदेष के सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए अलग से सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। हमने 60 वर्श से ऊपर के भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं, जिन्हें और कोई पेन्षन प्राप्त न हो, के लिए पेन्षन राषि में 65 प्रतिषत की वृद्धि कर इसे 200 रुपये से बढ़ाकर 330 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। हमारी सरकार ने 1998 में वार्शिक युद्ध जागीर को 600 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने फिर से इस युद्ध जागीर में 122 प्रतिषत की वृद्धि करके इसे 900 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का निर्णय लिया है। धर्मषाला स्थित युद्ध स्मारक के विषेश रख–रखाव हेतु, 2 लाख रुपये के विषेश अनुदान की घोशणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है। नालागढ़ में एक सैनिक विश्रामगृह का निर्माण किया जाएगा।

88ण हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने हेतु वचनबद्ध है। हमने सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय लिया है कि सरकारी कार्यालयों की विभिन्न सुरक्षा सेवाएं हिमाचल प्रदेष भूतपूर्व सैनिक निगम को 'आऊट सोर्स' की जाएं। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक निगम के माध्यम से कुछ परिवहन सेवा सम्बन्धी आवष्यकताएं भी पूरी की जाएंगी। निगम

को कम्प्यूटर 'डाटा ऐन्ट्री', सर्वेक्षण कार्य तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने जैसी अन्य तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे तकनीकी अर्हता प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार दिया जा सके। हमारे युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, प्रदेष सरकार हिमाचल प्रदेष सषस्त्र सेना में भर्ती कोटे को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से मामला उठाएगी।

कर्मचारी तथा पेन्षन भोगी कल्याण

89ण राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेन्षन भोगियों की जायज़ आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु हमारी सरकार अथक प्रयास करने में विष्वास रखती है। इसके दृश्टिगत कर्मचारियों तथा पेन्षन भोगियों की मांग की प्रतीक्षा किए बिना, हम उन्हें अन्तिरम राहत व मंहगाई भत्ते की किष्तें तीव्रता से ज़ारी करते रहे हैं। निश्पक्ष तथा पारदर्षी नीति के अनुसार लम्बी अवधि तक दिहाड़ी व अनुबन्ध पर रखे गए कर्मचारियों को भी नियमित किया गया है। हमारी सरकार ने दैनिक मज़दूरी में भी 33 प्रतिषत से अधिक वृद्धि कर इसे 75 रुपये से 100 रुपये किया था, जिसमें अब 10 प्रतिषत की और वृद्धि करके 110 रुपये कर दिया गया है। इन सभी कदमों से लगभग 4 लाख कर्मचारी एवं पेन्षन भोगी लाभान्वित हुए हैं, जिनमें अर्धसरकारी तथा स्वायत्त संस्थाओं के कर्मी भी षामिल हैं। हमारी सरकार द्वारा पेन्षन भोगियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की षीघ्र अदायगी को भी विषेश रूप से सुनिष्चित किया गया है।

90ण मुझे यह घोशित करते हुए हर्श हो रहा है कि नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे को 10 प्रतिषत से बढ़ाकर 30 प्रतिषत किया जाएगा। अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, सीमित सीधी भर्ती परीक्षा द्वारा यह अतिरिक्त 20 प्रतिषत कोटा भरेगा, जो पात्र

102 षैक्षणिक योग्यता वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से भरा जाएगा।

91ण जबसे हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली है, हमने अपने कर्मचारियों तथा पेन्षन भोगियों को 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक का अतिरिक्त लाभ पहुॅचाया है। मुझे विष्वास है कि मान्य सदन के सभी सदस्य इस तथ्य से सहमत होंगे कि प्रदेष की समग्र वित्तीय स्थिति के दृश्टिगत हमारी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की उचित आकांक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनषीलता दर्षाई है। साथ ही, सरकार अपने कर्मचारियों से यह अपेक्षा रखती है कि वे प्रदेष के तीव्र विकास के लिए लग्न तथा समर्पण की भावना से कार्य करें। सभी कर्मचारियों को आम आदमी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझने की आवष्यकता है।

बजट अनुमान

92ण अध्यक्ष महोदय, अब मैं बृहद् बजट अनुमानों का उल्लेख करता हूॅ। एफ0आर0बी0एम ;थ्त्ठडद्ध अधिनियम की अपेक्षा अनुसार मैं 2008–09 से 2011–12 तक की राज्य सरकार की मध्य अवधि राजकोशीय योजना को अलग से प्रस्तुत कर रहा हूॅ। अगले वेतन आयोग की संस्तुतियां अभी आनी षेश हैं, इसलिए इसके दायित्वों का सही आकलन इस मध्य अवधि राजकोशीय योजना में नहीं किया गया है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियां भी अक्तूबर, 2009 तक घोशित होनी हैं। 13वें वित्त आयोग के सामने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए राजस्व व्यय को क्रमषः 2010–11 में 14,556 करोड़ व 2011–12 में 14,144 करोड़ रुपये दर्षाया गया है। इस की तुलना में राज्य की अपनी आय 2010–11 में 4,357 करोड़ व 2011–12 में 4,849 करोड़ रुपये अनुमानित है। आय और व्यय का अन्तर 13वें वित्त आयोग से प्राप्त सहायतानुदान राषि से पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस वर्श की समाप्ति तक अनुमानित 1,500 करोड़ रुपये के ऋण लिए जाएंगे जो भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत सीमा के भीतर होंगे। इस प्रकार प्रदेष के दमज ऋण को लगभग 23,000 करोड़ रुपये तक सीमित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, 2008–09 से 2011–12 की मध्यम अवधि राजकोशीय योजना के फॉर्म 3 के विवरण अनुसार, 2593 करोड़

रुपये की बकाया गारंटियां हैं।

93ण 2009–10 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व आय 10,478 करोड़ रुपये तथा कुल राजस्व व्यय 10,222 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व लेखों में 256 करोड़ रुपये का अधिषेश रहेगा। पूंजीगत लेखों में कुल अनुमानित आय 2,439 करोड रुपये तथा ऋण लौटाने सहित कुल पूंजीगत व्यय 2,854 करोड़ रुपये होने की आषा है। 2009–10 में राजकोशीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.54 प्रतिषत तक अनुमानित है।

94ण 2009–10 में कुल 13,075 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। वेतन पर 3,748 करोड़, ब्याज अदायगी पर 2,053 करोड़, ऋण वापसी पर 981 करोड़ तथा पेन्षन पर 1,299 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

95ण बजट अनुमानों के अनुसार प्रत्येक 100 रुपये के व्यय के मुकाबले कुल राजस्व आय 80 रुपये है, जिसमें केन्द्र से धन प्राप्ति भी षामिल है। 20 रुपये के अन्तर को ऋण से पूरा करना होगा। राजस्व आय के प्रत्येक 100 रुपये में 26 रुपये अपने करों से प्राप्त राजस्व, 15 रुपये गैर कर राजस्व, 10 रुपये केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में तथा 49 रूपये केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त होंगे। प्रत्येक 100 रुपये के व्यय में 29 रुपये वेतन पर, 16 रुपये ब्याज की अदायगी, 8 रुपये ऋण की वापसी, 10 रुपये पेन्षन पर, 8 रुपये रखरखाव पर तथा षेश 29 रुपये प्रमुख विकासात्मक कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।

96ण संसाधन जुटाने की दिषा में, मैं पहले ही उल्लेख कर
चुका हूँ कि हमारी सरकार ने आमदनी बढ़ाने के लिए किस प्रकार असाधारण कदम उठाए हैं। हमारी गैर कर वसूलियां बहुत अच्छी रही हैं जिससे हमें राजकोशीय घाटे को नियंत्रित करने में मद्द मिली है। हम करों के माध्यम से भी राजस्व बढ़ाने हेतु नीतियां तैयार कर रहे हैं।

97ण मुझे यह घोशित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने 'सी0एफ0एल0 बल्ब', गैर–मार्का धुलाई साबुन तथा घी पर 'वैट' दर को 12.5 प्रतिषत से घटाकर 4 प्रतिषत करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने गृह रक्षकों की दैनिक मज़दूरी को 130 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया था। मुझे यह घोशित करते हुए प्रसन्नता है कि इस दर को बढ़ाकर 170 रुपये किया जाएगा। पंचायत चौकीदारों के पारिश्रमिक में 25 प्रतिषत की वृद्धि करके 800 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। हमने राज्य के सीमा क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के दायरे के सभी निवासियों के लिए प्रवेष षुल्क को 50 प्रतिषत घटाने का निर्णय लिया है। षौर्य पुरस्कार विजेताओं को इस षुल्क से छूट दी जाएगी। आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए, मैं यह घोशित करते हुए प्रसन्न हूँ कि बस किरायों में 10 प्रतिषत की कटौती की जा रही है।

98ण अगले वर्श के लिए बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। मैं अब बजट की मुख्य विषेशताओं तथा हमारी सरकार की उपलब्धियों का सारांष प्रस्तुत करना चाहूँगाः

- **2008–09 में 7.1 प्रतिषत की राश्ट्रीय औसत विकास दर के मुकाबले हिमाचल प्रदेष की विकास दर 7.7 प्रतिषत।**
- **राज्य की प्रति व्यक्ति आय 44,803 रुपये के मुकाबले अगले वर्श 50,000 रुपये से अधिक।**
- **औसत घरेलू आय 20,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक होगी।**
- **अगले वर्श का कुल बजट परिव्यय 13,075 करोड़ रुपये।**

- **2009–10 की वार्शिक योजना 2700 करोड़ रुपये।**
- **किसान मित्र बजट– 353 करोड़ रुपये की ''पंडित दीनदयाल किसान–बागवान समृद्धि योजना'' आरम्भ।**

- अगले वर्श सिंचाई के लिए 267 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- टमाटर, आलू, सेब तथा आम जैसी नकदी फसलों के लिए बीमा योजनाएं आरम्भ की जाएंगी।
- जैविक कृशि तथा कैंचुआ खाद को उच्च प्राथमिकता। 1.50 लाख कैंचुआ खाद इकाईयां स्थापित की जाएंगी।
- 1.25 लाख और मिट्टी परीक्षण कार्ड जारी किए जाएंगे। कुल संख्या 2.25 लाख हो जाएगी।
- एक वर्श में दूध के क्रय मूल्य में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि।
- 25 पशु औशधालय स्तरोन्नत तथा 19 नए।
- बेरोज़गार युवाओं को मछली पालन, मोती उत्पादन तथा व्यावसायिक ट्राऊट पालन का प्रषिक्षण दिया जाएगा।
- ''नरेगा'' से ग्रामीण बेरोज़गार 11,000 रुपये प्रति वर्श की आय अर्जित करने हेतु समर्थ। इसके लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रबन्धन।
- ''ग्रामीण विद्या उपासक योजना'' दोबारा लागू। सभी पूर्व पात्र ग्रामीण विद्या उपासक अनुबन्ध श्रठज अध्यापक बनेंगे।
- 8 साल की सेवा के उपरान्त पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव पदनामित करने का निर्णय।
- ग्राम रोज़गार सेवकों के लिए न्यूनतम सेवा षुल्क 1500 रुपये प्रतिमाह। तकनीकी सहायकों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह।
- पंचायत चौकीदारों के पारिश्रमिक में 25 प्रतिषत वृद्धि। 800 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह।
- दैनिक मज़दूरी दर 110 रुपये। गृह रक्षकों की दैनिक मज़दूरी दर 150 से बढ़ाकर 170 रुपये।

- ''इंदिरा आवास योजना'' तथा ''अटल आवास योजना'' के अन्तर्गत 9000 नए घरों का निमार्ण तथा 900 पुराने घरों की मुरम्मत।
- जल विद्युत परियोनाओं हेतु 'ए0डी0बी0' के साथ 4000 करोड़ रुपये का वित्त सहायता करार हस्ताक्षरित। 3600 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे।
- विद्युत परियोजनाओं की नई नीति द्वारा 24 से 56 प्रतिषत तक निषुल्क बिजली प्राप्त होगी।
- ''अटल बिजली बचत योजना'' द्वारा सभी घरों को 4 'सी0एफ0एल0 बल्ब' का मुफ्त वितरण। कुल लागत 80 करोड़ रुपये।

- सड़कों हेतु योजना परिव्यय में 58 प्रतिषत की वृद्धि। 304 करोड़ से बढ़ाकर 480 करोड़ रुपये किया गया।
- 300 से अधिक नयी बसें खरीदने हेतु एच0आर0टी0सी0 के लिए 43 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान। 77 करोड़ रुपये का गैर योजना प्रावधान। कुल प्रावधान 120 करोड़ रूपये।
- ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवाओं के लिए उदार परमिट आबंटन। इससे स्वरोज़गार के अवसरों में बढ़त तथा एच0आर0टी0सी0 के घाटे में कमी।
- सीमा क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए प्रवेष षुल्क में 50 प्रतिषत की कटौती। षौर्य पुरस्कार विजेताओं को पूरी छूट।
- पेय–जल आपूर्ति योजनाओं हेतु 182 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- बिलासपुर तथा कांगड़ा ज़िलों की 1171 बस्तिओं के लिए 3 मुख्य ग्रामीण पेय–जल परियोजनाएं आरम्भ। कुल लागत 172 करोड़ रुपये।
- अगले वर्श 2500 नए हैंड पम्प लगाकर कुल 20,000 हैंड पम्प की

स्थापना का लक्ष्य।

- अनुसूचित जाति उप योजना पिछले वर्श 231 करोड़ से 594 करोड़ तक बढ़ी। इसे अगले वर्श के लिए 668 करोड़ रुपये किया गया।

- पेन्षन राषि में 65 प्रतिषत की वृद्धि। 200 रुपये से 330 रुपये प्रतिमाह किया गया।
- प्रथम अप्रैल 2008 से 15,000 नए परिवार सामाजिक सुरक्षा पेन्षन से जोड़े गए। 2.52 लाख परिवार लाभान्वित।
- ''मातृषक्ति बीमा योजना'' के लाभों को एक वर्श में चौगुना किया गया। अब दुर्घटना में मृत्यु पर 1 लाख तथा एक अंग की क्षति पर 50,000 रुपये का प्रावधान।
- जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत 243 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- रोहतांग सुरंग निर्माण में तीव्रता लाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव।
- कांगड़ा ज़िले के लिए केन्द्रीय विष्वविद्यालय, निफ्ट ;छप्थ्ज्द्धए ˆ।ग्स्‍ प्लान्ट, बी0एस0एफ0 बटालियन, आपदा प्रबन्धन बटालियन, 'फूडक्राफ्ट इंसटिचयूट' केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाया।
- टांडा मैडिकल कॉलेज को एम्स ;।प्प्डैद्ध के बराबर स्तरोन्नत करने के लिए केन्द्र सरकार से 125 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाए गए।
- पालमपुर, सोलन, हमीरपुर, मण्डी तथा ऊना में मैडिकल कॉलेज खोलने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
- मण्डी में आई0आई0टी0 तथा मैडिकल कॉलेज हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त।
- 5 ज़िलों– किन्नौर, सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू तथा लाहौल–स्पिति के लिए बहुतकनीकी संस्थाएं स्वीकृत।

- बिलासपुर में एक नया इंजिनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा।
- सार्वजनिक निजी सांझेदारी में 12 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज तथा 28 नर्सिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेष में 10 निजी विष्वविद्यालय कार्य आरम्भ करेंगे।
- हिमाचल प्रदेष अब एक षिक्षा 'हब' बनेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे परिवारों हेतु सभी ज़िलों में बृहद् स्वास्थ्य बीमा योजना।
- रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से डॉक्टरों तथा अन्य मैडिकल स्टॉफ की भर्तियां।
- 225 डॉक्टरों व 262 नर्सों के पद भरे गए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के 175 व आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी।
- 350 करोड़ रुपये से अधिक की पर्यटन आधारभूत ढांचा परियोजनाएं ए0डी0बी0 को प्रस्तुत। स्वीकृत परियोजनाएं 90 प्रतिषत अनुदान के रूप में प्राप्त होंगी।
- नए पर्यटन स्थलों का 'इकोटूरिज़म' हेतु विकास।

- राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के आस–पास ''होम स्टे योजना'' पर बल।
- 'गेयटी थियेटर' महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र बनेगा।
- 17 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से हमीरपुर में भारतीय होटल प्रबन्धन संस्थान तथा धर्मषाला में 'फूडक्राफ्ट' इंसटिच्यूट' आरम्भ। आतिथ्य क्षेत्र में रोज़गार हेतु प्रतिवर्श 400 युवाओं को प्रषिक्षिण।
- धर्मषाला और हमीरपुर में 'सिंथैटिक एथेलेटिक ट्रैक्स' का निर्माण अगले वर्श सम्पन्न।

- पर्यावरण 'मास्टर प्लान' की तैयारी। सरकार द्वारा सभी पर्यावरणिक मामलों का व्यापक तरीके से निपटान।
- वन विभाग द्वारा 6000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अधिक से अधिक वनीकरण।
- औद्योगिक आधारभूत ढ़ांचे में सुधार।
- पात्र भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं की पेन्षन राषि को 200 से बढ़ाकर 330 रुपये प्रतिमाह किया गया।
- युद्ध जागीर में 122 प्रतिषत की वृद्धि। राषि 900 से बढ़ाकर 2000 रुपये।
- राज़्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेन्षन भोगियों को 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक के अतिरिक्त लाभ।

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा 10 प्रतिषत से बढ़ाकर 30 प्रतिषत।
- 'सी0एफ0एल0 बल्ब', गैर मार्का साबुन तथा घी पर कर दरों में कटौती।
- ग्रामीण सड़कों पर बसों के लिए पथकर में पूरी छूट। इससे एच0आर0टी0सी0 व निजी बस ऑपरेटर लाभान्वित।
- बस किरायों में 10 प्रतिषत की कटौती।

99ण अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि अपने बजट भाशण के माध्यम से मैंने सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं तथा हिमाचल प्रदेष की आर्थिक प्रगति व विकास को सुदृढ़ करने का उल्लेख किया है। हमारी सरकार के षासनकाल के प्रथम वर्श में की गई प्रगति समाज के सभी वर्गों के सामने स्पश्ट है। 2009–10 का बजट इस विकास को और तीव्रता से आगे बढ़ायेगा।

100ण अगला वित्त वर्श वेतन तथा पेन्षन के संषोधन के फलस्वरूप कठिन होगा। वर्तमान वर्श में ही बेहतर वित्तीय प्रबन्धन द्वारा हम अगले वर्श के प्रत्याषित दायित्वों को निभाने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। 2010 से 2015 की अवधि की वित्तीय कठिनाईयों को पार करने के लिए हमारी सरकार ने स्पश्ट तथा प्रभावी तरीके से 13वें वित्तायोग के सम्मुख अपना वित्तीय प्रकरण रखा है। वित्तायोग के साथ हम इस मामले पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखेंगे। हमें

विष्वास है कि वित्तायोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेगा।

101ण हमारी सरकार द्वारा प्रदेष की जो भावी वित्तीय बुनियाद स्थापित की गई है, वह वित्त विषेशज्ञों को पूर्ण रूप से स्पश्ट है। इस वर्श में उठाए गए कदमों के कारण वर्श 2017 से, केवल ऊर्जा के क्षेत्र में ही, 7000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त वार्शिक आय प्राप्त होगी। इस प्रकार की अतिरिक्त आय से हिमाचल प्रदेष के लोगों का एक अत्यन्त उज्जवल भविश्य होगा। हिमाचल प्रदेष की उड़ान की बुनियाद तैयार है।

102ण आगामी वर्श का बजट हमारी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेष के लोगों के समृद्ध भविश्य को बनाए रखने का निरन्तर प्रयास है। मैं यह बजट उनके उज्जवल भविश्य को समर्पित करता हूॅ।

103ण इन षब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को मान्य सदन को संस्तुत करता हूॅ।

जय हिन्द।

जय हिमाचल।